



Neutral Citation No.-2026:AHC:6879

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या-13580 वर्ष 2025

रंजीत पटेल @ विलुखु ..... आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य ..... प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: किरण यादव, रीमा पांडे, सर्वेश कुमार पांडेय, सौरभ राज श्रीवास्तव

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं - 66

माननीय न्यायमूर्ति श्री कृष्ण पहल

1. सूची को संशोधित किया गया है।
2. आवेदक के अधिवक्ता श्री सौरभ राज श्रीवास्तव, राज्य के राज्य विधि अधिकारी श्री आर.पी. पटेल को सुना और अभिलेखों पर रखी गई सामग्री का अवलोकन किया।
3. आवेदक ने मुकदमा लंबित रहने के दौरान धारा 302, 201, 34, 120बी भ०द०वि०, थाना-मिर्जामुराद, जिला: वाराणसी के तहत अपराध संख्या-269 वर्ष 2023 में जमानत मांगी है।
4. आवेदक के अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आवेदक पूरी तरह से निर्दोष है और प्रस्तुत मामले में उसे झूठा फंसाया गया है। उसका उक्त अपराध से कोई लेना-देना नहीं है। प्राथमिकी में देरी हो रही है और यह अस्पष्ट और गंजे आरोपों पर आधारित है। घटना का कोई चश्मदीद गवाह नहीं है। ये आरोप झूठे हैं।
5. आवेदक के अधिवक्ता ने आगे कहा है कि मृतक व्यक्ति के अंतिम संस्कार के समय सूचनाकर्ता बहुत मौजूद था। वह एक प्राकृतिक मृत्यु मर गई। मुकदमा आगे नहीं बढ़ रहा है और यह रुके हुए है। इस प्रकार, निकट भविष्य में विचारण के समापन की कोई संभावना नहीं है।



6. आवेदक के अधिवक्ता द्वारा आगे यह तर्क दिया जाता है कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक 23.11.2023 से जेल में बंद है, इस प्रकार कारावास की अवधि दो वर्ष से अधिक है। वह मुकदमे में सहयोग करने के लिए तैयार है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा कर दिया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।
7. राज्य विधि अधिकारी ने जमानत याचिका का पुरजोर विरोध किया है।
8. इस न्यायालय ने संबंधित विचारण न्यायालय से मुकदमे की स्थिति मांगी थी। दिनांक 15.12.2025 की उक्त स्थिति रिपोर्ट के अनुसार, आज तक एक भी गवाह से पूछताछ नहीं की गई है।
9. "जब तक दोषी साबित न हो जाए" का प्रसिद्ध सिद्धांत एक नियम के रूप में जमानत और अपवाद के रूप में कारावास की अवधारणा को जन्म देता है।
10. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा गारंटीकृत किसी व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार को केवल इसलिए नहीं छीना जा सकता है क्योंकि उस व्यक्ति पर अपराध करने का आरोप लगाया जाता है जब तक कि अपराध एक उचित संदेह से परे स्थापित नहीं हो जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि किसी का भी जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता तब तक नहीं छीनी जा सकती जब तक कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता है, और प्रक्रिया न्यायसंगत और उचित होनी चाहिए। उक्त सिद्धांत को उच्चतम न्यायालय द्वारा **सर्तेंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो और अन्य, (2022) 10 एस.सी.सी. 51** में दोहराया गया है।
11. उपरोक्त दृष्टिकोण को दोहराते हुए, **मनीष सिसोदिया बनाम प्रवर्तन निदेशालय, 2024 आई.एन.एस.सी. 595** के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने फिर से इस बात पर जोर दिया है कि कानून के बहुत अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत कि जमानत को सजा के रूप में नहीं रोका जाना चाहिए, को भुलाया नहीं जाना चाहिए। अब समय आ गया है कि न्यायालयों को इस सिद्धांत को स्वीकार करना चाहिए कि "जमानत एक नियम है और जेल एक अपवाद है"।
12. राज्य विधि अधिकारी किसी भी असाधारण परिस्थिति को सामने नहीं ला सके जो आवेदक को जमानत से इनकार कर दे।



13. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, पक्षों के अधिवक्ता द्वारा की गई प्रस्तुतियाँ, अभिलेखों पर साक्ष्य, प्राथमिकी की स्थापना में देरी को ध्यान में रखते हुए, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि निकट भविष्य में मुकदमे के समापन की कोई संभावना नहीं है क्योंकि आज तक एक भी गवाह की जांच नहीं की गई है, और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, प्रथम रूप से, न्यायालय का विचार है कि आवेदक ने जमानत के लिए मामला बनाया है। जमानत आवेदन की अनुमति है।

14. आवेदक- रंजीत पटेल @ विलुखू, जो उपरोक्त मामले के अपराध में शामिल है, को निम्नलिखित शर्तों के अधीन संबंधित अदालत की संतुष्टि के लिए एक व्यक्तिगत बांड और दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अलावा, रिलीज आदेश जारी करने से पहले, जमानतदारों का सत्यापन किया जाना चाहिए।

(i) आवेदक मुकदमे के दौरान साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

(ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/डराएगा नहीं।

(iii) आवेदक निर्धारित तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।

15. उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन के मामले में, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।

16. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत देने में की गई टिप्पणियों से गवाहों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में विचारण न्यायाधीश किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होगा।

जनवरी 12, 2026

विकास वर्मा

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)